भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1542

दिनांक 27.11.2019 को उत्तर देने के लिए

योजना आयोग का नीति आयोग के रूप में नामकरण

1542. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) नए नामकरण के पश्चात् नीति निर्माण निकाय में जिस प्रकार से सुधार हुआ उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इसके सदस्यों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय

तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रकों और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 01 जनवरी, 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया है। सरकार के समर्पित थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग से राष्ट्र के भविष्य की कार्यनीतिक रूपरेखा तैयार करते हुए एक निदेशात्मक भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। इससे राष्ट्रीय विकास एजेंडा को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार (केंद्र और राज्य, दोनों) को विशिष्ट कार्यनीतिक, प्रकार्यात्मक और तकनीकी सुझाव प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग से नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और उनके प्रभाव के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है।

(ख) नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रकों यथा कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, जल संसाधन, शहरीकरण, ऊर्जा, परिवहन, इत्यादि के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को निदेशात्मक और नीतिगत सुझाव (इनपुट) प्रदान करता रहा है। इसका प्रयास नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल प्रबंधन को एकसाथ नीति निर्माण और कार्यान्वयन के केन्द्र में लाना है। यह राज्यों को सतत आधार पर संरचनाबद्ध सहायता और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। नीति आयोग द्वारा विकसित आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ने बेहतर साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के लिए परिव्ययों से परिणाम-आधारित शासन की दिशा में आमूल परिवर्तन सृजित किया है। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग

ने स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, समग्र जल प्रबंधन, संधारणीय विकास लक्ष्यों, आदि जैसे मानदंडों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के लिए कई सूचकांक आरंभ किए हैं। यह देश में 112 अल्प-विकसित जिलों का विकास करने के उद्देश्य से 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' का संचालन कर रहा है जिसके तहत जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों और संगठनों के बीच प्रभावी अभिसरण हासिल करने और शासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 'अटल नवप्रवर्तन मिशन' अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से देश-भर में नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल है। नीति आयोग ने नव भारत@75 के लिए कार्यनीति दस्तावेज भी जारी किया है जिसमें विकास के प्रेरकों, अवसंरचना, समावेशन और शासन के साथ 41 प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत अनुशंसाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों के साझे विज़न के विकास में अपनी एकीकृत भूमिका के निष्पादन में, नीति आयोग राज्यों, सिविल सोसाइटी और अन्य थिंक टैंकों के साथ सक्रियता से विचार-विनिमय करता है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****